

State-wise Targets for Assisting the Scheduled Tribe Families for the VIth Five-Year Plan

S.No.	Name of the State and Union Territory	Target for assisting the families
1.	Andaman & Nicobar	73,00
2.	Andhra Pradesh	50,000
3.	Assam	—*
4.	Bihar	3,00,000
5.	Gujarat	3,50,000
6.	Himachal Pradesh	21,600
7.	Karnataka	—*
8.	Kerala	16,000
9.	Madhya Pradesh	6,18,000
10.	Maharashtra	—*
11.	Manipur	—*
12.	Orissa	5,50,000
13.	Rajasthan	50,000
14.	Sikkim	—*
15.	Tamil Nadu	15,000
16.	Tripura	—*
17.	Uttar Pradesh	3,100
18.	West Bengal	1,08,275
19.	Goa Daman & Diu	1,516
Approximate total target		23 lakhs tribal families

*Targets are under revision.

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मकान विदेशी दूतावासों को किराये पर देने से संबंधित नियम

8794, श्री विजय कुमार यादव :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी दिल्ली में अपने मकान विदेशी दूतावासों और विदेशी राजनयिकों को किराए पर दे सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियमों में क्या प्रावधान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी. वेकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (प्राचरण) नियमावली, 1984 के नियम 18-क और अखिल भारतीय सेवाओं तथा रेलवे सेवाओं को शासित करने वाले प्राचरण नियमों के तदनुसूची उपबंधों के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में धारित किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में किसी पट्टे की मंजूरी के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या समुत्थान के साथ कोई संबन्ध नहीं करेगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए "विहित प्राधिकारी" के समूह 'क' सरकारी सेवकों के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय विभाग समूह "ख" सरकारी सेवकों के मामले में विभागाध्यक्ष और समूह "ग" तथा समूह "घ" सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अभि-प्रेत है।